



## झारखंड में पैक्स का डजिटलीकरण

### चर्चा में क्यों?

[राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक \(नाबारड\)](#) ने घोषणा की है कि [डजिटलीकरण अभियान](#) के दूसरे चरण के अंतर्गत वह झारखंड की 1,297 [प्राथमिक कृषि ऋण समितियों \(PACS\)](#) का कंप्यूटरीकरण करेगा।

### मुख्य बंदि

- **पृष्ठभूमि**
  - सहकारिता मंत्रालय की [केंद्र-प्रायोजित डजिटलीकरण परियोजना](#) ग्रामीण क्षेत्रों में [प्राथमिक कृषि ऋण समितियों \(PACS\)](#) को आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों के केंद्र में परिवर्तित करने हेतु कार्य कर रही है।
  - राज्य में कुल **4,454 PACS** हैं, जो ग्रामीण समुदायों की सेवा करने वाली प्राथमिक स्तर की सहकारी ऋण संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं।
  - परियोजना के **प्रथम चरण** में नाबारड ने **1,500 PACS** का सफलतापूर्वक डजिटलीकरण किया है।
- **कंप्यूटरीकृत PACS की विशेषताएँ:**
  - आधुनिक PACS को [हार्डवेयर और विशेष सॉफ्टवेयर](#) दोनों से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे [राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एकीकरण](#) सुनिश्चित होगा।
  - इससे वे विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होंगे, जिनमें शामिल हैं:
    - [प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना \(PMFBY\)](#) तथा [प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण](#) जैसी सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन।
    - उर्वरक और बीज जैसे कृषिआदानों का वितरण।
    - [जन औषधि केंद्र](#), पेट्रोल एवं गैस डीलरशिप तथा ग्राहक सेवा केंद्रों का संचालन।
    - कृषिउपज के भंडारण हेतु ग्रामीण गोदामों की स्थापना।
- **नाबारड की भूमिका:**
  - नाबारड ने [ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष \(RIDF\)](#) के अंतर्गत **100 करोड़ रुपये** का कोष स्थापित किया है, जिसका उपयोग भंडारण सुविधाओं और संबंधित [बुनियादी ढाँचे](#) के निर्माण में किया जाएगा।
  - PACS कंप्यूटरीकरण की नोडल एजेंसी के रूप में नाबारड नमिन दायित्व भी निभा रहा है।
  - [नए डजिटल सिस्टम के उपयोग में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।](#)
  - [नरंतर तकनीकी सहायता प्रदान करना।](#)
  - [बुनियादी ढाँचे के विकास को सुविधाजनक बनाना।](#)

## राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबारड)

- नाबारड एक [विकास बैंक](#) है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्तपोषण प्रदान करने वाला [शीर्ष बैंकिंग संस्थान](#) है।
- नाबारड एक [वैधानिक निकाय](#) है, जिसे [राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981](#) के अंतर्गत वर्ष **1982** में स्थापित किया गया।
- इसका [मुख्यालय मुंबई](#) (देश की वित्तीय राजधानी) में स्थित है।
- कृषि के अतिरिक्त, नाबारड [लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों](#) तथा [ग्रामीण परियोजनाओं](#) के विकास के लिये भी उत्तरदायी है।

## प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)

- ये मूलतः [ऋण समितियाँ](#) हैं, जो संबंधित [राज्य के सहकारी समिति अधिनियम](#) के तहत पंजीकृत हैं।
- PACS प्राथमिक स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं, जो किसानों को [सुलभ ऋण, बैंकिंग सेवाएँ और कृषि सहायता](#) प्रदान करती हैं।
- ये [ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों \(DCCB\)](#) और [राज्य सहकारी बैंकों \(SSB\)](#) के साथ भारत की त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना का आधार बनाती हैं।
- 1.08 लाख PACS में से लगभग 63,000 कंप्यूटरीकरण के उन्नत चरण में हैं तथा सरकार का लक्ष्य उनमें से **80,000 को पूर्णतः डजिटल** बनाना है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/digitization-of-pacs-in-jharkhand>

